Year	As per cent of GDP
Average 1990-91-1997-98	3.7
(RE)-Revised Estimate;	
(BE)-Budget Estimate;	

Subsidies constitute only one item of revenue expenditure, and the revenue deficit is influenced by a host of other fiscal parameter such as tax and non-tax receipts, components of revenue expenditure which include interest payments etc. It has been the government's endeavour to rationalise subsidies and to focus subsidies to final goods and services with a view to maximising their impact on the target population at minimum cost.

Deferring of World Bank loan

5430. SHRI NARENDRA MOHAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that World Bank has deferred $ 200 million project loans;

(b) if so, what were these project for which these loans were to be obtained; and

(c) whether Government are thinking of explaining India's view point to World Bank so that these loans are not deferred and are available for Indian projects as scheduled?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): (a) and (b) In response to requests from several Executive Directors the World Bank on May 26 and June 2, 1998 postponed the consideration of following five proposed operations in India:—

(i) The Power Grid II Project (US $ 450 million).

(ii) Renewable Energy II Project (US $ 130 million)

(iii) Haryana State Highway Project (US $ 275 million)

(iv) U.P. Diversified Agriculture Support Project (US $ 130 million).

(v) Orissa Health System Development Project (US $ 76.4 million).

Subsequently, out of the above five, Serial No. (iv) and (v) have been approved on July 1, 1998.

In addition, the World Bank has also approved following loans as per schedule:—

(i) Andhra Pradesh Economic Restructuring Project (US $ 543.2 million) on June 25, 1998.

(ii) Women and Child Development Project (US $ 300 million) on July 1, 1998.

(c) The Government has been pursuing actively in this regard.

विभिन्न बैंकों के लाभ / हानि की स्थिति

4531. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1997-98 के दौरान विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों, विदेशी बैंकों तथा निजी बैंकों की बैंकवार लाभ-हानि की स्थिति क्या रही है; और

(ख) घाटे में चल रहे राष्ट्रीयकृत बैंकों को लाभ में लाने के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है और क्या सरकार की इन्हें बंद करने या इनका विलय करने की कोई योजना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० जनार्दनम): (क) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 31.3.1998 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों, विदेशी बैंकों और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों को हुए लाभ / हानि की स्थिति विवरण I, II व III में दी गई है **(नीचे देखिए)**।

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक / सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं / कर रहे हैं:—

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों के उच्च कार्यपालकों के साथ विभिन्न पैरामीटरों के मुकाबले में और कार्यनिष्पादन के लिए पहले की गई प्रतिबद्धताओं की तुलना में उनके कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने के लिए विभिन्न कार्य निष्पादन पैरामीटरों के संबंध में वार्षिक विचार-विमर्श करता है। बैंक, कारोबार और कार्यनिष्पादन का उच्च स्तर प्राप्त करने, लाभप्रदता में सुधार करने, अनिष्पादित अग्रिमों (एनपीए) की वसूली तथा आंतरिक लेखा